आकाशवाणी केन्द्र शिमला
19.08.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा– भविष्य में आर्थिक संपन्नता के आधार पर तीन सौ यूनिट फ्री बिजली देने पर विचार करेगी सरकार।
- स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा– हिमकेयर योजना की 3 सौ 64 करोड़ रूपए की देनदारी लंबित– योजना में सुधार के प्रयास जारी।
- राज्य सरकार ने प्रदेश में आपदा प्रभावितों के राहत पैकेज को बढ़ाकर 7 लाख 70 हज़ार रूपए किया।
- प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन से तीन बार किया वॉकआउट।
- राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा विधानसभा में की गई टिप्पणियों को लेकर भाजपा ने इस सत्र में मंत्री के बहिष्कार का लिया निर्णय।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भविष्य में आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों खास कर होटलियर या उद्यमियों को 3 सौ यूनिट बिजली फ्री देने पर सरकार विचार करेगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक सुधीर शर्मा और केवल सिंह पठानिया के संयुक्त सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को एक सौ 25 यूनिट बिजली निशुल्क दे रही है और इसे अभी तक बंद नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के आग्रह पर प्रदेश में 12 से 15 हजार लोगों ने स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ी है, जिससे बिजली बोर्ड को 59 लाख रुपए का लाभ हुआ है। सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के विधायक व मंत्रियों ने भी यह सब्सिडी छोड़ दी है और विपक्ष भी इसमें अपना योगदान करे तो अच्छा संदेश जाएगा। इससे पहले, मूल सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष से 20 फरवरी 2025 तक कैबिनेट रैंक प्राप्त नेताओं के बिजली बिलों पर सरकार द्वारा 17 लाख 95 हज़ार 8 सौ 79 रुपये का व्यय किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक आई.पी.डी.एस. और आर.डी.एस.एस. योजनाओं के तहत कुल 6 लाख 52 हज़ार 9 सौ 55 स्मार्ट मीटर शिमला, धर्मशाला शहरों तथा शिमला जोन के तहत आने वाले कुछ क्षेत्रों में लगाए जा चुके हैं।

हिमकेयर योजना को लेकर विधायक विनोद कुमार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमकेयर योजना की 3 सौ 64 करोड़ रूपए की लंबित देनदारी है और इस योजना में जो धांधली हुई है, उसमें सुधार किया जा रहा है। विधायक विनोद कुमार ने मंत्री के जवाब से असंतुष्टि जताई। इसी बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जवाब में हस्तक्षेप को उठे, लेकिन विपक्षी सदस्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और वे अपनी सीटों से उठे और फिर नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्ष की गैरमौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर अच्छी योजना है और उनकी सरकार इसमें सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना पर अभी तक 5 सौ 50 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष केवल सनसनी फैलाने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हैल्थ केयर पर तीन हजार करोड़ रुपए खर्च कर आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत किसी का भी इलाज नहीं रुकेगा।

चर्चा

मानसून सत्र के दूसरे दिन नियम 67 के तहत विपक्ष की ओर से आपदा को लेकर लाए प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। चर्चा शुरू करते हुए विधायक नीरज नैयर ने मनरेगा के नए नियमों पर आपत्ति जताई और इस मुद्दे को केंद्र से उठाने की मांग की। चर्चा के दौरान विधायक लोकेन्द्र कुमार ने आपदा राहत पैकेज को लेकर सवाल उठाए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में आपदा पीड़ितों को दिया जा रहा राहत पैकेज 7 लाख रूपए नहीं बल्कि 7 लाख 70 हज़ार रूपए का है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार अपने राहत पैकेज को बढ़ाया है और इस आपदा राहत पैकेज को सराज ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अधिसूचित किया गया है। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने बरसात से पहले नदियों व नालों की डि–सिल्टिंग करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया तो आने वाले दिनों में जिला ऊना में भारी नुकसान होगा। उन्होंने डि–सिल्टिंग के लिए बोली लगाने का सुझाव दिया जिससे सरकार को आय होगी और भारी बारिश से नुकसान भी नहीं होगा। चर्चा में विधायक राम कुमार चौधरी, सुधीर शर्मा, मोहन ब्राक्टा, सुरेन्द्र शौरी और राकेश कालिया ने भाग लिया।

वॉकआउट

प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। आज जहां विपक्षी सदस्य एक घंटे के भीतर 3 बार सदन से बाहर गए वहीं विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान हिमकेयर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। दूसरी बार प्रश्नकाल के दौरान प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर की गई टिप्पणियों के विरोध में पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। विपक्ष द्वारा बार–बार वॉकआउट करने पर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा दिशाहीन हो चुकी है और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती।

*1 घंटे में चार वॉकआउट करना ये इस चीज को दिखलाता है कि दिशा विभिन्न भारतीय जनता पार्टी। वो चर्चा ही नहीं करना चाहते ।वो हर चीज पर खड़े हो जाते हैं। मैं कोई रेक्टिफाई कर रहा हूं अपनी बात को, क्रेश्चन के साथ ऐसा प्रीवियसली हम भी विधायक रहे हैं जो मुख्यमंत्री होते थे वह और बीच में भी रेक्टिफाई कर लेते थे जब उनके पास सूचना आती थी उसपर खड़े हो जाते हैं। वॉकआउट करना इस बात को इंगित करता है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका बहुत ऊपर है । चर्चा कीजिए विषय पर लाइए आप तर्क के साथ बात कीजिए और उसके बाद अगर उसका जवाब नहीं मिलता है तो वॉकआउट करना बनता है ,आप बात सुने बगैर ही वॉकआउट कर देते हो।*

उधर, विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि गरीबों के मुफ्त इलाज को सरकार ने बंद कर दिया है और प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं निम्न स्तर पर पहुंच चुकी हैं।

*हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाओं का सत्यानाश जिस प्रकार से किया है वर्तमान सरकार में ऐसा कभी आज से पहले नहीं हुआ है। निम्न स्तर पर आज तक स्वास्थ्य की सुविधाएं जो आज हिमाचल प्रदेश में चले गई हैं आज प्रश्न के उत्तर में जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि अभी भी तीन सौ चौंसठ, करोड़ बीस लाख उनतीस हज़ार सात रुपये हिम केयर के*

*अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकार को देना है और इसी कारण से सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इलाज करने से वहाँ पर मना कर दिया है तो यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है।*

बहिष्कार

प्रदेश में प्राकृतिक आपदा को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा विधानसभा में की गई टिप्पणियों को लेकर भाजपा ने इस सत्र में मंत्री के बहिष्कार का निर्णय लिया है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि राजस्व मंत्री द्वारा सदन में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणियों की पार्टी कड़ी निंदा करती है।

वहीं, राजस्व मंत्री ने कहा है कि विपक्ष लोकतंत्र की परंपराओं को तोड़ रहा है और वे संविधान व सच्चाई के आधार पर जवाब देते रहेंगे।